



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2039]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 22, 2015/भाद्र 31, 1937

No. 2039]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 22, 2015/BHADRA 31, 1937

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 22 सितम्बर, 2015

का.आ. 2588(अ).—भारत सरकार में पूर्व पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1533 (अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित प्रारूप अधिसूचना, जिसे केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी करने का प्रस्ताव करती है, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार, जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है; जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है; और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा;

यदि कोई व्यक्ति प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्ताव पर सुझाव या आक्षेप देना चाहे तो वह लिखित में, अपने सुझाव या आक्षेप इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर केन्द्रीय सरकार के विचारार्थ सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, अलीगंज नई दिल्ली-110003, (ई-मेल: mk.singh 65@ias.niv.in and Sridhar_mef@nic.in. को भेज सकेगा;

प्रारूप अधिसूचना

2009 की एसएलपी (सी) सं. 19628-19629 में 2011 की आई.ए.संख्या 12-13 में दीपक कुमार इत्यादि बनाम हरियाणा राज्य और अन्य इत्यादि मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के तारीख 27-2-2012 के आदेश में लघु खनिजों के खनन हेतु खनन पट्टा क्षेत्र का विचार किए बिना पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति आज्ञापक है;

माननीय उच्चतम न्यायालय के उपर्युक्त आदेश के परिणामस्वरूप ऐसे मामलों की संख्या में काफी वृद्धि हो गई है, जिनको अब पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति अभिप्राप्त करना अपेक्षित है;

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने अपने आदेश तारीख 13-1-2015 में बालू खनन के संबंध में लघु खनिजों हेतु समूहों में खनन पट्टों के लिए पर्यावरणीय अनापत्ति पर नीति बनाने के लिए निदेश दिए हैं;

राज्य सरकारों ने लघु खनिज और त्रिक अर्थ के पर्यावरणीय अनापत्ति की प्रक्रिया को सरल और कारगर बनाने के लिए अभ्यावेदन किया है;

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य सरकारों के परामर्श से धारणीय बालू खनन पर समूहों के लिए पर्यावरणीय अनापत्ति पर उपबंधों, जिला पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण के सृजन का ब्यौरा देते हुए और सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं का स्रोत से गंतव्य तक खनन की गई सामग्री को ले जाने के लिए उपयोग करते हुए बालू खनन की उचित मॉनिटरी पर दिशानिर्देश तैयार किए हैं;

अतः अब केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (घ) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (v) के खंड (5) और उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के अधीन यथाअपेक्षित प्रारूप अधिसूचना प्रकाशित करती है, जो इसके अंतिम प्रकाशन की तारीख को और से उक्त अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करेगी, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, --

(क) पैरा 2 में “उक्त अनुसूची में” शब्दों के पश्चात् निम्नलिखित शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

“और जिला स्तर पर, उक्त अनुसूची में, प्रवर्ग ख2 के अधीन आने वाले मामलों के लिए जिला पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डीईआईए)”;

(ख) पैरा 3 के पश्चात् निम्नलिखित पैरा अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"3 क. जिला पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण :—

- (1) केंद्रीय सरकार द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन चार सदस्यों से मिलकर, जिसके अंतर्गत अध्यक्ष और सदस्य सचिव है, जिला पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिसे इसमें इसके पश्चात् डीईआईए कहा गया है, गठित किया जाता है।
- (2) जिला मजिस्ट्रेट या जिला कलक्टर डीईआईए का अध्यक्ष होगा;
- (3) जिला खनन अधिकारी या भू विज्ञानी या राज्य के संबंधित जिले के खनन या भू विज्ञान विभाग का वरिष्ठतम अधिकारी डीईआईए का एमएस होगा;
- (4) डीईआईए के अन्य सदस्यों में प्रभागीय वन अधिकारी (यदि किसी जिले में एक से अधिक प्रभागीय वन अधिकारी है, तो वरिष्ठतम) और एक विशेषज्ञ होगा। विशेषज्ञ, यथास्थिति, प्रभाग के प्रभागीय आयुक्त या राज्यों में मुख्य वन संरक्षक द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा। पात्रता मानदंड पूर्ण करने वाले विशेषज्ञ के निबंधन और अर्हताएं इस अधिसूचना के परिशिष्ट-VII में दिए गए हैं।

- (5) विशेषज्ञ सदस्य के सिवाए डीईआईए के सदस्य, जो संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के सेवारत अधिकारी हैं, पदेन सदस्य होंगे;
- (6) जिला स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, जिसे इसमें इसके पश्चात् डी ई ए सी कहा गया है, नौ सदस्यों से मिलकर बनेगी, जिसके अंतर्गत अध्यक्ष या सदस्य सचिव है।
- (7) संबंधित राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के जिले में सिंचाई विभाग का वरिष्ठतम कार्यपालक अभियंता डी ई ए सी का अध्यक्ष होगा।
- (8) जिले का वरिष्ठतम उप-मंडल अधिकारी डी ई ए सी का सदस्य सचिव होगा।
- (9) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का प्रतिनिधि, जिले में वरिष्ठतम उपमंडल अधिकारी (वन), दूर संवेदी विभाग या भू विज्ञान विभाग या राज्य धरातल जल विभाग का एक अधिकारी, एक जिला पंचायत सदस्य, और, यथास्थिति, प्रभागीय आयुक्त या मुख्य वन संरक्षक द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले तीन विशेषज्ञ सदस्य डी ई ए सी के अन्य सदस्य होंगे। पात्रता मानदंड पूर्ण करने वाले विशेषज्ञों के निबंधन और अर्हताएं इस अधिसूचना के परिशिष्ट 8 में दी गई हैं।
- (10) विशेषज्ञ सदस्य के सिवाए डी ई ए सी के सदस्य, जो संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के सेवारत अधिकारी हैं, पदेन सदस्य होंगे।
- (11) जिला कलेक्टर किसी अभिकरण को डीईआईए और डीईएसी के सचिवालय के रूप में कार्य करने हेतु अधिसूचित करेगा और उसके कानूनी कृत्यों के लिए सभी वित्तीय और संभार-तंत्र संबंधी सहायता प्रदान करेगा।
- (12) जिला स्तरीय पर्यावरण संघात निर्धारण प्राधिकारी और जिला स्तरीय विशेषज्ञ शक्तियों का प्रयोग करेगी और समय समय पर यथा संशोधित मूल्यांकन समिति उक्त अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट प्रक्रिया का अनुसरण करेगी।
- (13) जिला स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करेगी और प्रत्येक मामले में सर्वसम्मति पर पहुंचने का प्रयास करेगी और यदि सर्वसम्मति पर नहीं बन पाए तो बहुमत का अभिमत अभिभावी होगा।";

(ग) पैरा 4 में उप-पैरा (iii) के पश्चात् निम्नलिखित पैरा अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(iv) पांच एकड़ से कम या उसके बराबर पट्टे का लघु खनिज के खनन से संबंधित बी2 प्रवर्ग परियोजनाओं में जिला स्तरीय पर्यावरण संघात निर्धारण प्राधिकारी से पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त करना अपेक्षित होगा। जिला स्तरीय पर्यावरण संघात निर्धारण प्राधिकारी का विनिश्चय इस अधिसूचना के लिए यथा गठित जिला स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की सिफारिशों पर आधारित होगा।";

(घ) पैरा 5 के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात् :—

ईएसी, एसईएसी और डीईएसी प्रत्येक मास में कम से कम एक बार बैठक करेगी।

'5 स्क्रीनिंग, विस्तार और मूल्यांकन समितियां:—

केन्द्रीय सरकार में समान विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (ईएसी), राज्य या राज्य संघ राज्यक्षेत्र स्तर पर एसीएसी तथा जिला स्तर पर डीईएसी क्रमशः प्रवर्ग 'ए' 'बी' और बी2 प्रवर्ग में परियोजना या क्रियाकलाप को स्क्रीन, विस्तार और मूल्यांकन करेंगे। ईएसी, एससीएसी और डीईएसी प्रत्येक मास न्यूनतम एक बार बैठक करेंगे।

(क) ईएसी की संरचना परिशिष्ट 6 में दी गई है। राज्य या राज्य संघ राज्यक्षेत्र स्तर पर एसईएसी समान संरचना वाली संबद्ध राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के परामर्श से केन्द्रीय सरकार द्वारा गठित की जाएगी, जिला स्तर पर डीईएसी पैरा 3(क) में दी गई संरचना के अनुसार केन्द्रीय सरकार द्वारा गठित की जाती है।

(ख) केन्द्रीय सरकार संबद्ध राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों की सहमति से प्रशासनिक सुविधा और खर्च के कारणों के लिए एक राज्य या संघ राज्यक्षेत्र से अधिक के लिए एक एसईएसी गठित कर सकेगी;

(ग) ईएसी और एसईएसी प्रत्येक तीन वर्ष के पश्चात् पुनर्गठित की जाएगी;

(घ) संबद्ध ईएसी, एसईएसी और डीईएसी के परियोजना या क्रियाकलाप से संबंधित किसी स्थल (स्थलों) का निरीक्षण कर सकेगी जिनके संबंध में आवेदक जो निरीक्षण के लिए आवश्यक सुविधाएं को उपलब्ध कराएगा, कम से कम सात दिन की पूर्व सूचना के साथ स्क्रिनिंग या व्याप्तिकरण या मूल्यांकन के प्रयोजनों के लिए पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति की वांछा की गई है।

(ड.) ईएसी, एसईएसी और डीईएसी सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करेगी। अध्यक्ष प्रत्येक मामले में सर्वसम्मति पर पहुंचने का प्रयास करेगा और यदि सर्वसम्मति पर नहीं पहुंचा जा सकता बहुमत का अभिमत अभिभावी होगा।

(इ) पैरा 6 के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात् :—

"6 पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति (ईसी) के लिए आवेदन :—

सभी मामलों में पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति के लिए आवेदन इसके साथ उपाबद्ध प्ररूप 1 और प्ररूप 1क में किया जाएगा जैसा कि परिशिष्ट 2 में प्ररूप 1ड में प्रवर्ग बी2 परियोजनाओं के अधीन लघु खनिजों के खनन के लिए दिया गया है, यदि लागू हो, जैसा कि परिशिष्ट 8 में दिया गया है, आवेदक द्वारा स्थल पर कोई संनिर्माण क्रियाकलाप आरंभ करने या भूमि तैयार करने के पूर्व परियोजना और/या उन क्रियाकलापों जिनसे आवेदन संबंधित है, के लिए संभावित स्थलों की पहचान के पश्चात् किया जाएगा। आवेदक आवेदन के साथ पूर्व संभाव्यता परियोजना रिपोर्ट की एक प्रति प्रस्तुत करेगा, प्रवर्ग बी2 परियोजना के अधीन लघु खनिजों का खनन करने के लिए पर्यावरणीय अनापत्ति हेतु आवेदन डीईआईए को प्रस्तुत किया जाएगा, सिवाय यह कि संनिर्माण परियोजनाओं या क्रियाकलापों (अनुसूची की मद 8) के मामले में प्ररूप 1 और प्ररूप 1क के अतिरिक्त, पूर्व संभाव्यता की रिपोर्ट के बजाए संकल्पनात्मक योजना की एक प्रति प्रदान की जाएगी";

(च) पैरा 7 में,—

(i) उप-पैरा (i) में, "प्रक्रम 1-स्क्रिनिंग" शीर्ष के अधीन, विद्यमान उप-पैरा को उप-पैरा (1) के रूप में संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार संख्यांकित उप-पैरा के पश्चात् निम्नलिखित उप-पैरा अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(ख) परिशिष्ट 9 में यथाविनिर्दिष्ट मामले लघु खनिजों के खनन के लिए पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति से छूट प्राप्त होंगे।"

(ii) उप-पैरा (ii) के पश्चात् निम्नलिखित उप-पैरा अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"7 (iii) रेत खनन के लिए जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार करना

(क) रेत खनन के लिए जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को तैयार करने के लिए विहित प्रक्रिया परिशिष्ट 10 में दी गई है।

(ख) कलस्टर स्थिति सहित लघु खनिज खनन के लिए पर्यावरणीय अनापत्ति की विहित प्रक्रिया परिशिष्ट 11 में दी गई है";

(छ) पैरा 8 में,—

(i) "ईएसी या एसईएसी" अक्षरों और शब्द के स्थान पर "ईएसी या एसईएसी या डीईएसी" शब्द और अक्षर रखे जाएंगे;

(ii) "विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति या राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति", शब्दों के स्थान पर, जहां कहीं वे आते हैं,

"विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति या राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति या जिला स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति" शब्द रखे जाएंगे;

(ज) पैरा 10 में, उप-पैरा (iii) के पश्चात् निम्नलिखित पैरा अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(iv) रेत खनन के लिए पर्यावरणीय अनापत्ति को मॉनीटर करने के लिए विहित प्रक्रिया परिशिष्ट-12 में दी गई है।";

(i) अनुसूची में,—

(1) मद 1(क) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित मद और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"1(क)	(i) खनिजों का खनन	गैर कोयला खान पट्टे की बाबत खनन पट्टा क्षेत्र के ≥ 50 हैक्टेयर कोयला खान पट्टे की बाबत खनन पट्टा क्षेत्र का >150 हैक्टेयर पर खनन क्षेत्र को ध्यान में न रखकर एस्बस्टॉस खनन	गैर कोयला खान पट्टे की बाबत खनन पट्टा क्षेत्र के ≥ 50 हैक्टेयर कोयला खान पट्टे की बाबत खनन पट्टा क्षेत्र का <150 हैक्टेयर	साधारण शर्तें निम्न लिखित के सिवाय लागू होंगी: (i) 'बी2' प्रवर्ग के लघु खनिजों की खनन परियोजनाओं या क्रियाकलाप (खनन पट्टा क्षेत्र का 5 हैक्टेयर तक) (ii) अंतरराज्यिक सीमा के कारण नदी रेत खनन परियोजनाएं
	(ii) राष्ट्रीयपार्कों या अभ्यारणों या प्रवाल भित्तियों, पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील क्षेत्रों के माध्यम से गुजरने वाली पंक पाइप लाइनें (कोयला इग्नाइट और अन्य अयस्क)	सभी परियोजनाएं		टिप्पण: (i) खनिज पूर्वोक्षण छूट प्राप्त है";

(ज) परिशिष्ट 6 के पश्चात् निम्नलिखित परिशिष्ट अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

"परिशिष्ट 7

(पैरा 3क देखें)

डीईआईए और डीईएसी में विशेषज्ञों के लिए अर्हताएं और निबंधन

अर्हताएं : एम ए/एम एस सी डिग्री या बी.टेक/बीई/बी.आर्क. डिग्री या विधि में डिग्री।

- अनुभव :** उपर्युक्त पात्रता मानदंड पूर्ण करने वाला कोई व्यक्ति, जिसके पास पारिस्थितिकी मापन/मानीटरी, नदी पारिस्थितिकी/वनस्पतीय/जीव जन्तु संबंधी प्रबंधन, जीव विज्ञान/वानिकी/वन्य जीव/खनन/भू-विज्ञान विशेषज्ञ/पर्यावरणीय अर्थव्यवस्था/सामाजिक अर्थव्यवस्था के संबंध में आंकड़ों का विश्लेषण और निर्वचन के दस वर्ष के अनुभव सहित या संबंधित विषय में पांच वर्ष के अनुभव सहित डाक्टरी डिग्री (पीएचडी)
- आयु :** सत्तर वर्ष से अधिक नहीं; ऐसे किसी व्यक्ति की अनुपलब्धता के विषय में आयु में पांच वर्ष की छूट दी जा सकेगी
- कार्यकाल :** विशेषज्ञ सदस्यों का अधिकतम कार्यकाल तीन वर्ष के प्रत्येक कार्यकाल के दो कार्यकालों के लिए होगा।

परिशिष्ट 8

(पैरा 6 देखें)

प्ररूप 1ड

श्रेणी 'बी2' के अधीन लघु खनिजों के खनन के लिए आवेदन

(I) आधारभूत जानकारी

- खनन पट्टा स्थल का नाम :
- अवस्थिति/स्थल (जीपीएस को-आर्डिनेट्स) :
- खनन पट्टे का आकार (हेक्टेयर) :

- (iv) खनन पट्टे की क्षमता (टीपीए) :
- (v) खनन पट्टे की अवधि :
- (vi) परियोजना की अनुमानित लागत :
- (vii) संपर्क जानकारी :

(II) पर्यावरणीय संवेदनशीलता

क्र.सं.	क्षेत्र	दूरी किलोमीटर में/ब्यौरे
1	संबंधित नदी, उप नदी, नाले पर निकटतम रेल/सड़क पुल से परियोजना स्थल की दूरी	
2	अवसंरचनात्मक सुविधाओं से दूरी रेल लाइन राष्ट्रीय राजमार्ग राज्य राजमार्ग प्रमुख जिला सड़क अन्य कोई सड़क विद्युत संचरण लाइन पोल/टावर नहर पेयजल पम्प हाउस के लिए इनटेक सिंचाई नहर पम्प के लिए इनटेक	
3	अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशनों के अधीन संरक्षित क्षेत्र, उनके पारिस्थितिकीय, भू-दृश्य, सांस्कृतिक या अन्य संबंधित मूल्य के लिए राष्ट्रीय या स्थानीय विधान	
4	ऐसे क्षेत्र, जो पारिस्थितिकीय कारणों – वेटलैंड, वाटर कोर्सेस या अन्य जल निकायों, तटीय जोन के लिए महत्वपूर्ण या संवेदी है।	
5.	प्रजनन, घोषला बनाने, चारा देने, विश्राम करने अति शीत ऋतुवन के लिए, वनस्पति या प्राणि जगत की संरक्षित, महत्वपूर्ण या संवेदनशील प्रजातियों द्वारा उपयोग किए गए क्षेत्र	
6.	अंतर्देशीय, तटीय, समुद्री या भूमिगत-जल	
7.	राज्य, राष्ट्रीय सीमाएं	
8.	मनोरंजन या अन्य पर्यटकों, तीर्थ यात्री क्षेत्रों तक पहुंच के लिए जनता द्वारा उपयोग किए गए मार्ग या सुविधाएं	
9.	रक्षा संस्थापन	
10.	सघन जनसंख्या वाले या निर्मित क्षेत्र	
11.	संवेदनशील मानव निर्मित भू-उपयोगों द्वारा अधिगृहीत क्षेत्र(अस्पताल, पूजा स्थल, सामुदायिक सुविधाएं)	
12.	महत्वपूर्ण, उच्च गुणवत्ता या दुर्लभ संसाधनों वाले क्षेत्र (भू-जल संसाधन, सतही संसाधन, वानिकी, कृषि, मत्स्य, पर्यटन, खनिज)	
13.	ऐसे क्षेत्र जो प्रदूषण या पर्यावरणीय नुकसान से पहले ही ग्रस्त हैं (उन क्षेत्रों में जहां विद्यमान विधिक पर्यावरणीय मानक अधिक हैं)	

14.	प्राकृतिक संकट के लिए संवेदनशील क्षेत्र जो परियोजना के लिए वर्तमान पर्यावरणीय समस्याओं को उत्पन्न कर सकते हैं (भूकंप, धंसाव, भूस्खलन, भूमि कटाव, बाढ़ आना या अत्यधिक या प्रतिकूल जलवायु दशाएं)	
15.	क्या भू-जल, रिचार्ज के लिए फटन/दरार पर या उसके निकट अवस्थित खनन स्थल का प्रस्ताव किया गया है।	

परिशिष्ट-9**[पैरा 7(i) (ख) देखिए]****लघु खनिजों के खनन के रूप में समझे जाने से कतिपय मामलों की छूट**

निम्नलिखित मामले पूर्व पर्यावरण अनापत्ति की अपेक्षा के प्रयोजन के लिए खनन संक्रियाओं के रूप में नहीं समझे जाएंगे, अर्थात् :—

1. मिट्टी के बर्तन तैयार करने के लिए कुम्हारों (पोटर) द्वारा उनके रुढ़ियों के अनुसार हाथ से साधारण चिकनी मिट्टी या रेत का निष्कर्षण।
2. मिट्टी की टाइल निर्माताओं द्वारा जो मिट्टी की टाइलें तैयार करते हैं, हाथ से साधारण चिकनी मिट्टी या रेत का निष्कर्षण।
3. किसानों द्वारा बाढ़ के पश्चात् कृषि के खेत में रेत भंडारों का हटाया जाना।
4. गांव में निजी उपयोग या सामुदायिक उपयोग के लिए ग्राम पंचायत में स्थित स्रोतों से रेत और साधारण मिट्टी का रुढ़िजन्य निष्कर्षण।
5. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार और गारंटी स्कीमों और अन्य सरकार द्वारा प्रायोजित स्कीमों में आरंभ किए गए ग्रामीण जलाशयों या तालाबों की गाद निकालने, ग्रामीण सड़को, बंदों का संनिर्माण जैसे सामुदायिक संकर्म।
6. बांधों, जलाशयों, बंधिका, बराजों, नदियों और नहरों की उनके अनुरक्षण तथा रखरखाव के प्रयोजन के लिए निष्कर्षण और गाद निकालना।

परिशिष्ट-10**[पैरा 7(iii) (क) देखिए]****जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के तैयार किए जाने के लिए प्रक्रिया**

जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (पोषणीय रेत खनन मार्गदर्शी सिद्धांत) के तैयार किए जाने का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित को सुनिश्चित करना है:

जहां खनन अनुज्ञात किया जा सकता है वहां प्रत्यायन/निक्षेपण के क्षेत्रों की पहचान और जहां खनन को प्रतिषिद्ध किया जाना चाहिए वहां अवसंरचनात्मक संरचनाओं तथा संस्थापनों का भू कटाव तथा समीप्यता की पहचान और आपूरण की वार्षिक दर की संगणना और उस क्षेत्र में खनन के पश्चात् आपूरण के लिए समय अनुज्ञात करना।

रिपोर्ट में निम्नलिखित संरचनाएं हैं:

1. प्रस्तावना
2. जिले में खनन क्रियाकलाप का अवलोकन
3. अवस्थान, क्षेत्र वाले जिले में खनन पट्टों की सूची तथा वैधता की अवधि
4. गत तीन वर्षों में प्राप्त स्वामिस्व/राजस्व के व्योरे
5. गत तीन वर्षों में रेत, बजरी, लघु खनिजों के उत्पादन के व्योरे
6. जिले की नदियों में तलछटी के निक्षेपण की प्रक्रिया

7. जिले की साधारण प्रोफाइल
8. जिले में भूमि उपयोग पैटर्न: वन, कृषि, उद्यान कृषि, खनन आदि
9. जिले की भू-आकृति विज्ञान
10. वर्षा: मासवार
11. भूगर्भ विज्ञान और खनिज संपदा।

उपरोक्त के अतिरिक्त रिपोर्ट में निम्नलिखित अंतर्विष्ट होंगे:

- (क) नदी या सरिता और अन्य रेत स्रोत के जिला वार ब्यौरे
- (ख) रेत/ कंकड़/समग्र संसाधनों की जिला वार उपलब्धता।
- (ग) रेत और समग्रों की विद्यमान खनन पट्टों के जिले वार ब्यौरे।

जिले में भूगर्भ विभाग/ सिंचाई विभाग/ वन विभाग/ लोक निर्माण विभाग/भूजल बोर्ड/सुदूर संवेदी विभाग/खनन विभाग आदि द्वारा डीआईईए प्रयोग करते हुए एक सर्वेक्षण किया जाना चाहिए।

मुख्य नदियों के वर्णन सहित अपवहन प्रणाली

क्रम सं.	नदी का नाम	अपवाहित क्षेत्र(वर्ग कि.मी.)	जिले में अपवाहित प्रतिशत क्षेत्र

महत्वपूर्ण नदियों और सरिताओं की मुख्य विशेषताएं

क्रम सं.	नदी/सरिता का नाम	जिले में कुल लंबाई (कि.मी. में)	उदगम का स्थान	उदगम पर अक्षांश

खनिज छूट के लिए सिफारिश की गई नदी/सरिता का भाग	खनिज छूट के लिए सिफारिश किए गए क्षेत्र की लंबाई (कि.मी.)	खनिज छूट के लिए सिफारिश किए गए क्षेत्र की औसत चौड़ाई (मीटर में)	खनिज छूट के लिए सिफारिश किए गए क्षेत्र (वर्ग मीटर में)	खननीय संभाव्य खनिज (मीट्रिक टन में) (कुल संभाव्य खनिज का 60 प्रतिशत)

संभाव्य खनिज (मीट्रिक टन में)

शिलाखंड	बजरी	रेत	कुल खननीय संभाव्य खनिज

कुल भंडार

क्रम सं.	नदी/सरिता	खनिज छूट के लिए सिफारिश किए गए क्षेत्र की लंबाई (कि.मी.)	खनिज छूट के लिए सिफारिश किए गए क्षेत्र की औसत चौड़ाई (मीटर में)	खनिज छूट के लिए सिफारिश किए गए क्षेत्र (वर्ग मीटर में)	खननीय संभाव्य खनिज (मीट्रिक टन में) (कुल संभाव्य खनिज का 60 प्रतिशत)	खनिज छूट के लिए सिफारिश किए गए क्षेत्र की लंबाई (कि.मी.)
जिले के लिए योग						

उप मंडल मजिस्ट्रेट सिंचाई विभाग से अधिकारी एसपीसीबी, वन विभाग, भू-गर्भ विज्ञान/खनन अधिकारी से मिलकर बनी एक उप मंडल समिति को प्रत्येक स्थल पर दौरा करना चाहिए और खनन के लिए स्थल की उपयुक्तता या उसके प्रतिषेध पर सिफारिश करनी चाहिए।

संभाव्य खनिज की संगणना करने के लिए अंगीकृत पद्धति।

संभाव्य खनिज फील्ड अन्वेषण और नदी/सरिताओं के आवाह क्षेत्र के भू-गर्भ विज्ञान के आधार पर संगणित किया जाएगा। स्थल की दशाओं और अवस्थिति के अनुसार खननीय खनिज की गहराई को परिभाषित किया गया है। किसी नदी या सरिता में खनिज के हटाए जाने के लिए क्षेत्र का भू-आकृति विज्ञान और अन्य कारकों पर निर्भर रहते हुए विनिश्चय किया जा सकता है, यह विशिष्ट नदी/सरिता के क्षेत्र का 50 प्रतिशत से 60 प्रतिशत तक हो सकता है। उदाहरणार्थ कुछ पहाड़ी राज्यों में एक मीटर की गहराई तक शिलाखंड, नदी से निकाली गई बजरी, जैसे खनिज संघटकों संसाधन खनिज के रूप में माना जाता है। चिकनी मिट्टी और गाद जैसे अन्य संघटकों को विशिष्ट नदी/सरिता के संभाव्य खनिज की संगणना करते समय अपशिष्ट के रूप में छोड़ दिया जाता है।

परिशिष्ट-11**[पैरा 7(iii) (ख) देखिए]****कलस्टर में लघु खनिजों के खनन की पर्यावरणीय अनापत्ति के लिए प्रक्रिया**

कलस्टर में लघु खनिज के खनन की उपाप्ति हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगा:

(1) राज्यों द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़े(पोषणीय रेत खनन मार्गदर्शी सिद्धांत 2015 के अनुसार) यह दर्शाते हैं कि लघु खनिजों के लिए अधिकतर खनन पट्टों का पट्टा क्षेत्र पांच हेक्टेयर से कम है। यह रिपोर्ट किया गया है कि पांच हेक्टेयर से अधिक के क्षेत्र वाले नदी में फैलाव प्राप्त करने वाले पहाड़ी राज्य बहुत ही असामान्य हैं। इसलिए नदी रेत खनन सहित लघु खनिजों के लिए पट्टे का आकार परिस्थितियों के अनुसार राज्यों द्वारा अवधारित किया जाएगा।

(2) लघु खनिजों का खनन अधिकतर कलस्टरों में है। पर्यावरण संघात मूल्यांकन। पर्यावरण प्रबंध योजना (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् 3 ईआईए/ईएमपी कहा गया है) सभी संभव बाह्यताओं को अच्छादित करने के लिए संपूर्ण कलस्टर के लिए तैयार

करनी अपेक्षित हैं। इन रिपोर्टों में कलस्टर की वहन क्षमता, परिवहन और संबद्ध मुद्दों, आपूर्ण और रिचार्ज मुद्दे, कलस्टर क्षेत्र के भू जल विज्ञान को भी सम्मिलित करना चाहिए। राज्य की ईआईए/ईएमपी रिपोर्ट राज्य या राज्य द्वारा नाम निर्देशित अभिकरण/ कलस्टर में परियोजना प्रस्तावकों का समूह/ कलस्टर में परियोजना प्रस्तावक द्वारा तैयार की जाएगी।

(3) संपूर्ण कलस्टर के लिए एक लोक परामर्श होगा जिसके पश्चात् कलस्टर के लिए अंतिम ईआईए/ईएमपी रिपोर्ट तैयार की जाएगी।

(4) ईसी के लिए आवेदन किया जाएगा और व्यष्टिक परियोजना प्रस्तावक को जारी किया जाएगा।

(5) कलस्टर ईआईए/ईएमपी रिपोर्ट के ब्यौरे उस कलस्टर के प्रत्येक ईसी में परिलक्षित किए जाएंगे और डीईएसी, एसईएसी और ईएसी यह सुनिश्चित करेगी कि ईआईए/ईएमपी अध्ययन से उद्भूत प्रशम्य उपाय उस कलस्टर के व्यष्टिक परियोजना प्रस्तावकों के ईसी में ईसी शर्तों के रूप में पूर्णतय परिलक्षित किए गए हैं।

कलस्टर सहित लघु खनिजों के पर्यावरणीय अनापत्ति पर अपेक्षाओं की स्कीम संबंधी प्रस्तुति

पट्टे का क्षेत्र (हेक्टेयर)	परियो जना का प्रवर्ग	ईआईए/ईएमपी की अपेक्षा	लोक सुनवाई की अपेक्षा	ईसी की अपेक्षा	ईआईए/ईएमपी कौन तैयार कर सकता है	ईसी के लिए कौन आवेदन करेगा	ईसी का मूल्यांकन करने/प्रदान करने का प्राधिकार	ईसी अनुपालन का मानीटर करने का प्राधिकार
व्यष्टिक खान पट्टे के आधार पर रेत खनन का ईसी प्रस्ताव								
0-5 हेक्टेयर	'बी 2'	प्ररूप -1 पीएफआर और अनुमोदित खान योजना	नहीं	हां	परियोजना प्रस्तावक	परियोजना प्रस्तावक	डीईएसी/डी ईआईएए	जिला कलक्टर एसपीसीबी सीपीसीबी पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय अभिकरण
>5 हेक्टेयर और 50 हेक्टेयर तक	'बी 1'	हां	हां	हां	परियोजना प्रस्तावक	परियोजना प्रस्तावक	एसईएसी/एसईआईएए	
50 हेक्टेयर और उससे अधिक	ए	हां	हां	हां	परियोजना प्रस्तावक	परियोजना प्रस्तावक	ईएसी/ पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय अभिकरण	
कलस्टर स्थिति में लघु खनिज खनन का ईसी प्रस्ताव								
5 हेक्टेयर से कम खान पट्टे का कलस्टर	'बी 2'	प्ररूप -1 पीएफआर और अनुमोदित खान योजना	नहीं	हां	राज्य, राज्य अभिकरण, परियोजना प्रस्तावकों का समूह, परियोजना प्रस्तावक	परियोजना प्रस्तावक	डीईएसी/डी ईआईएए	जिला कलक्टर एसपीसीबी सीपीसीबी पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय अभिकरण
50 हेक्टेयर से कम सभी व्यष्टिक पट्टे सहित किसी भी	'बी 1'	हां	हां	हां	राज्य, राज्य अभिकरण, परियोजना प्रस्तावकों का समूह,	परियोजना प्रस्तावक	एसईएसी/एसईआईएए	

आकार के खनिज पट्टों का कलस्टर					परियोजना प्रस्तावक			
50 हेक्टेयर से अधिक सभी व्यष्टिक पट्टे सहित किसी भी आकार के खनिज पट्टों का कलस्टर	ए	हां	हां	हां	राज्य, राज्य अभिकरण, परियोजना प्रस्तावकों का समूह, परियोजना प्रस्तावक	परियोजना प्रस्तावक	ईएसी/ पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	

परिशिष्ट-12
[पैरा 10(iv) देखिए]

रेत खनन की मानीटरिंग के लिए प्रक्रिया

1. टी.पी. की सुरक्षा विशेषता निम्नानुसार होगी:

- (क) आईबीए अनुमोदित एमआईसीआर पेपर पर मुद्रित।
- (ख) विशिष्ट बार कोड
- (ग) विशिष्ट क्यूआर कोड
- (घ) प्लायक शाही पृष्ठ भूमि
- (ङ.) अदृश्य शाही चिन्ह
- (च) शून्य विद्युद्वाही
- (छ) जल चिन्ह

2. खान पट्टा स्थल पर अपेक्षा

- (क) लघु आकार भू-खंड (पांच हेक्टेयर तक): एंड्रायड आधारित स्मार्ट फोन
- (ख) बृहत् आकार के भू-खंड (पांच हेक्टेयर से अधिक): सीसीटीवी कैमरा, पर्सनल कंप्यूटर(पीसी), इंटरनेट कनेक्शन, पावर बैक-अप
- (ग) खान पट्टा स्थल के पहुंच नियंत्रण
- (घ) प्रयोग किए गए यान के ट्रेलर के आकार के आधार पर निकाले गए खनिजों के बाहर के भार के लिए व्यवस्था या अनुमान

3. परिवहन अनुज्ञा पत्र या प्राप्ति का स्कैन करना और सर्वर पर अपलोड करना:

- (क) वेबसाइट: खनन साइट पर प्राप्ति की स्कैनिंग, साफ्टवेयर का प्रयोग करते हुए बारकोड स्कैनर और कंप्यूटर के माध्यम से की जा सकती है।

- (ख) एंड्रायड आवेदन: स्मार्ट फोन का उपयोग करते हुए एंड्रायड, खनन साइट पर स्कैनिंग एंड्रायड आवेदन का प्रयोग करके की जा सकती है।

इसमें सिम कार्ड पर इंटरनेट की उपलब्धता की जरूरत होगी।

- (ग) एसएमएस: टी.पी./प्राप्ति को मोबाइल के माध्यम से एसएमएस भेजकर भी सर्वर पर अपलोड किया जा सकता है जब टी.पी./प्राप्ति अपलोडिड कर दी जाती है तो विशिष्ट इनवायस को उसकी विधिमान्य अवधि के साथ उत्पन्न की जाती है।

4. प्रणाली का प्रस्तावित कार्यक्रम:

ऊपर पैरा 1 में प्रगणित सुरक्षा विशेषताओं वाली टी.पी./प्राप्ति को राज्य खनन विभाग प्रिंट करे और उन्हें जिला कलक्टर के माध्यम से खान पट्टा धारक को जारी करे। इन परिवहन अनुज्ञा पत्रों या प्राप्तियों के जारी किए जाने पर उन्हें उस खान पट्टा

क्षेत्र के संबंध में सर्वर पर अपलोड किया जाएगा। प्रत्येक प्राप्ति अधिमान्यता पूर्व नियत मात्रा के साथ होनी चाहिए। इसलिए कुल मात्रा जारी की गई प्राप्तियों के लिए अवधारित कर दी जाती है।

जब परिवहन अनुज्ञा पत्र या प्राप्ति बार कोड स्कैन हो जाता है और इनवायस उत्पन्न हो जाती है तो विशिष्ट बारकोड का प्रयोग कराया जाता है और उसका विधिमान्य समय सर्वर पर अभिलिखित किया जाता है। इसलिए खान से निकाली गई सामग्री के परिवहन के सभी ब्यौरे सर्वर पर पकड़े जा सकते हैं और परिवहन अनुज्ञा पत्र या प्राप्ति का पुनः प्रयोग किया जा सकता है।

5. मार्ग पर जांच

खनिज खनिज वहन करने वाले यानों की जांच के प्रयोजन के लिए भेजे गए कर्मचारिवृंद वेबसाइट एंड्रायड आवेदन और एसएमएस का प्रयोग करते हुए उन्हें स्कैन करके परिवहन अनुज्ञा पत्र या प्राप्ति की विधिमान्यता की जांच करने की स्थिति में होने चाहिए।

6. यान की खराबी

यान खराब हो जाने की दशा में परिवहन अनुज्ञा पत्र या प्राप्ति की विधिमान्यता यान की खराबी की रिपोर्ट करने के लिए विनिर्दिष्ट प्ररूप में चालक द्वारा एसएमएस भेजकर बढ़ाई जाएगी। सर्वर में यह सूचना और रजिस्टर होगी और खराबी को रजिस्टर करेगा। राज्य भी ऐसा कॉल सेंटर स्थापित कर सकता है जो ऐसे यानों की खराबी को रजिस्टर कर सकता है और विधिमान्यता की अवधि को बढ़ा सकता है। यान के पश्चातवर्ती पुनः चालू होने को भी सर्वर/ कॉल सेंटर को उसी प्रकार रिपोर्ट करना चाहिए।

7. यानों की खोज करना

स्रोत से गंतव्य तक यान का मार्ग चैक बिंदुओं आरएफआईडी टैगों और जीपीएस ट्रेकिंग का प्रयोग करके प्रणाली के माध्यम से खोजा जा सकता है।

8. चेतावनी/रिपोर्टजनन और पुनर्विलोकन कार्रवाई

प्रणाली दैनिक उठाई रिपोर्ट, यान लॉग/इतिहास आवंटन के प्रति उठाई और कुल उठाई जैसे भिन्न भिन्न पैरामीटरों पर आवधिक रिपोर्ट तैयार करने के लिए प्राधिकारियों को समर्थ बनाएगी। इस प्रणाली का ऑटो मेल्स/एसएमएस उत्पन्न करने के लिए उपयोग किया जा सकता है। इससे जिला कलक्टर और मजिस्ट्रेट सभी सुसंगत ब्यौरे प्राप्त करने में समर्थ होंगे और अनियमितता में संलिप्त पाई जाने वाली किसी साइट की स्कैनिंग सुविधा को ब्लाक करने के लिए प्राधिकारी को समर्थ बनाएगा। जब कभी कोई प्राधिकारी अवैध रेत का परिवहन करने वाले किसी यान की तलाशी लेगा तो वह सर्वर पर रजिस्टर कराएगा और अधिकारी के लिए यह आज्ञापक होगा कि वह की गई कार्रवाई रिपोर्ट में इसे भरे। प्रत्येक तलाशी लिए गए यान का पीछा किया जाना चाहिए।

खान से निकाले गए खनिज की मानीटरी, पर्यावरणीय अनापत्ति शर्तें और पर्यावरण प्रबंध योजना का प्रवर्तन जिला कलक्टर और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा। पर्यावरण अनापत्ति शर्तों के प्रवर्तन की मानीटर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और इस प्रयोजन के लिए मंत्रालय द्वारा नामनिर्देशित अभिकरण द्वारा की जा सकती है।

[फा. सं. जैड-11013/98/2014आईए-II (एम)]

मनोज कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना सं. 1533(अ), तारीख 24 सितंबर, 2006 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनमें निम्नानुसार पश्चातवर्ती संशोधन किए गए:—

1.	का.आ. 1737(अ), तारीख 11 अक्टूबर, 2007;
2.	का.आ. 3067(अ), तारीख 1 दिसंबर, 2009;
3.	का.आ. 695(अ), तारीख 4 अप्रैल, 2011;

4.	का.आ. 2896(अ), तारीख 13 दिसंबर, 2012;
5.	का.आ. 674(अ), तारीख 13 मार्च, 2013;
6.	का.आ. 2204(अ), तारीख 19 जुलाई, 2013;
7.	का.आ. 2555 (अ), तारीख 21 अगस्त, 2013;
8.	का.आ. 2559(अ), तारीख 22 अगस्त, 2013;
9.	का.आ. 2731(अ), तारीख 9 सितंबर, 2013;
10.	का.आ. 562(अ), तारीख 26 फरवरी, 2014;
11.	का.आ. 637(अ), तारीख 28 फरवरी, 2014;
12.	का.आ. 1599(अ), तारीख 25 जून, 2014;
13.	का.आ. 2601(अ), तारीख 7 अक्टूबर, 2014;
14.	का.आ. 2600(अ), तारीख 9 अक्टूबर, 2014;
15.	का.आ. 3252(अ), तारीख 22 दिसंबर, 2014;
16.	का.आ. 382(अ), तारीख 3 फरवरी, 2015;
17.	का.आ. 811(अ), तारीख 23 मार्च, 2015;
18.	का.आ. 996(अ), तारीख 10 अप्रैल, 2015;
19.	का.आ. 1142(अ), तारीख 17 अप्रैल, 2015;
20.	का.आ. 1141(अ), तारीख 19 अप्रैल, 2015;
21.	का.आ. 1834(अ), तारीख 6 जुलाई, 2015 ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd September, 2015

S.O. 2588(E).—The following draft of the notification, further to amend the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest number S.O.1533(E), dated the 14th September, 2006 (hereinafter referred to as the said notification) which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the Public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposal contained in the draft notification may forward the same in writing for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jor Bagh Road, Aliganj, New Delhi-110 003, or send it to the e-mail address at:— mk.singh65@ias.nic.in and Sridhar-mef@nic.in.

DRAFT NOTIFICATION

Whereas, in pursuance to the order of Hon'ble Supreme Court dated 27.02.2012 in I.A. No.12-13 of 2011 in Special Leave Petition (C) No.19628-19629 of 2009, in the matter of Deepak Kumar etc. Vs. State of Haryana and Others etc., prior Environmental Clearance has now become mandatory for mining of minor minerals irrespective of the area of mining lease;

And whereas, as a result of the above said order of Hon'ble Supreme Court, the number of cases which are now required to obtain prior environment clearance has increased substantially;

And whereas, the Hon'ble National Green Tribunal, *vide* its order dated 13.01.2015 in the matter regarding sand mining has directed for making a policy on environmental clearance for mining leases in cluster for minor minerals;

And whereas, the State Governments have represented for streamlining the process of environmental clearance of minor mineral and brick earth;

And whereas, the Ministry of Environment, Forest and Climate Change in consultation with State Governments has prepared Guidelines on Sustainable Sand Mining detailing the provisions on environmental clearance for cluster, creation of District Environment Impact Assessment Authority and proper monitoring of sand mining using information technology and information technology enabled services to track the mined out material from source to destination;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 read with clause (d) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby publishes the draft notification as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, which shall on and from the date of its final publication make the following amendments in the said notification, namely:—

In the said notification,-

(a) In paragraph 2, after the words “in the said Schedule”, the following words shall be inserted, namely:—

“and at District level, the District Environment Impact Assessment Authority (DEIAA) for matters falling under Category ‘B2’ in the said Schedule”;

(b) after paragraph 3, the following paragraph shall be inserted, namely:—

“3 A. District Level Environment Impact Assessment Authority:—

(1) A District Level Environment Impact Assessment Authority hereinafter referred to as the DEIAA shall be constituted by the Central Government under sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 comprising of four members including a Chairman and a Member-Secretary.

(2) The District Magistrate or District Collector shall be the Chairman of the DEIAA.

(3) The District Mines Officer or Geologist or senior most officer of Mines or Geology Department of the concerned district of the State shall be the Member-Secretary of the DEIAA..

(4) The other two members of the DEIAA shall be the Divisional Forest Officer (senior most in case there are more than one Divisional Forest Officers in a district) and one expert. The expert shall be nominated by the Divisional Commissioner of the Division or Chief Conservator of Forests in States, as the case may be. The term and qualifications of the expert fulfilling the eligibility criteria are given in Appendix VII to this notification.

(5) The members of the DEIAA who are serving officers of the concerned State Government or the Union territory Administration shall be *ex-officio* members except the expert member.

(6) The District Level Expert Appraisal Committee hereinafter referred to as the DEAC shall comprise of nine members, including a Chairman and a Member-Secretary.

(7) The senior most Executive Engineer, Irrigation Department in the district of respective State Governments and Union territory Administration shall be the Chairman of the DEAC.

(8) The senior most Sub-Divisional Officer of the district shall be the Member-Secretary of the DEAC.

(9) The representative of the State Pollution Control Board, senior most Sub-Divisional Officer (Forest) in the district, officer of Remote Sensing Department or Geology Department or State Ground Water Department, one Zila Panchayat member, and three expert members to be nominated by the Divisional Commissioner or Chief Conservator of Forest, as the case may be, shall be the other members of the DEAC. The term and qualifications of the experts fulfilling the eligibility criteria are given in Appendix VII to this notification.

(10) The members of the DEAC who are serving officers of the concerned State Government or the Union territory Administration shall be *ex-officio* members except the expert members.

(11) The District Collector shall notify an agency to act as secretariat for the DEIAA and the DEAC and he shall provide all financial and logistic support for their statutory functions.

(12) The DEIAA and DEAC shall exercise the powers and follow the procedure as specified in the said notification, as amended from time to time.

(13) The DEAC shall function on the principle of collective responsibility and the Chairman shall endeavor to reach a consensus in each case and if consensus cannot be reached, the view of the majority shall prevail.”;

(C) in paragraph 4, after sub-paragraph (iii), the following sub-paragraph shall be inserted, namely:—

“(iv) The ‘B2’ Category projects pertaining to mining of minor mineral of lease area less than or equal to five hectare shall require prior environmental clearance from DEIAA. The DEIAA shall base its decision on the recommendations of DEAC, as constituted for this notification.”;

(d) for paragraph 5, the following paragraph shall be substituted, namely:—EAC, SEAC’s and DEACs shall meet at least once every month.

“5. Screening, Scoping and Appraisal Committees:—

The same Expert Appraisal Committee (EAC) at the Central Government, SEACs at the State or Union territory level and DEAC at the district level shall screen, scope and appraise projects or activity in category ‘A’ ‘B’ and ‘B2’ respectively. EAC, SEACs and DEACs shall meet at least once every month.

(a) The composition of the EAC shall be as given in Appendix VI. The SEAC at the State or, the Union territory level is hereby constituted by the Central Government in consultation with the concerned State Government or the Union territory Administration with identical composition. DEAC at the district level shall be constituted by the Central Government as per the composition given in paragraph 3 A.

(b) The Central Government may with the prior concurrence of the concerned State Governments or the Union territory Administration constitute one SEAC for more than one State or Union territory for reasons of administrative convenience and cost.

(c) The EAC and SEAC shall be reconstituted after every three years.

(d) The authorized members of the EAC, SEACs and DEACs concerned, may inspect any site connected with the project or activity in respect of which the prior environmental clearance is sought for the purpose of screening or scoping or appraisal with prior notice of at least seven days to the applicant who shall provide necessary facilities for the inspection.

(e) The EAC, SEACs and DEACs shall function on the principle of collective responsibility. The Chairperson shall endeavor to reach a consensus in each case and if consensus cannot be reached the view of the majority shall prevail.”;

(e) for paragraph 6, the following paragraph shall be substituted, namely:—

“6 Application for Prior Environmental Clearance (EC):—

An application seeking prior environmental clearance in all cases shall be made in the prescribed Form I annexed herewith and Form IA, if applicable, as given in Appendix II, Form 1M for mining of minor minerals under Category ‘B2’ projects, if applicable, as given in Appendix VIII, after the identification of prospective site(s) for the project and/or activities to which the application relates, before commencing any construction activity, or preparation of land, at the site by the applicant. The applicant shall furnish, along with the application, a copy of the pre-feasibility project report, an application form for environmental clearance for mining of minor minerals under Category B2 projects shall be submitted to the DEIAA, except that, in case of construction projects or activities (item 8 of the Schedule) in addition to Form I and Form IA, a copy of the conceptual plan shall be provided, instead of pre-feasibility report”;

(f) in paragraph 7,-

(i) in sub-paragraph (i), under the heading “I.Stage (1)- Screening:”, the existing sub-paragraph shall be lettered as sub-paragraph “(A)” and after sub-paragraph as so lettered, the following sub-paragraph shall be inserted, namely:—

“(B) The cases as specified in Appendix IX shall be exempted from prior EC.” ;

(ii) after sub-paragraph (ii), the following sub-paragraph shall be inserted, namely:—

“7 (iii) Preparation of District Survey Report for Sand Mining:

(a) The prescribed procedure for preparation of District Survey Report for sand mining is given in Appendix X.

(b) The prescribed procedure for environmental clearance for mining of minor minerals including cluster situation is given in Appendix XI.”;

(g) in paragraph 8,-

(i) for the letters and word “EAC or SEAC”, the words and letters “EAC or SEAC or DEAC” shall be substituted;

(ii) for the words “Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee” wherever they occur, the words “Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee or District Level Expert Appraisal Committee” shall be substituted;

(h) in paragraph 10, after sub-paragraph (iii), the following sub-paragraph shall be inserted, namely:—

“(iv) The prescribed procedure for monitoring of sand mining is given in Appendix XII.”;

(i) in the Schedule,-

(i) for item 1 (a) and the entries relating thereto, the following item and entries shall be substituted, namely:—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“1(a)	<p>(i) Mining of minerals</p> <p>(ii) Slurry pipelines (coal lignite and other ores) passing through national parks or sanctuaries or coral reefs, ecologically sensitive areas.</p>	<p>≥50 ha of mining lease area in respect of non-coal mine lease</p> <p>>150 ha of mining lease area in respect of coal mine lease</p> <p>Asbestos mining irrespective of mining area</p> <p>All projects.</p>	<p><50 ha of mining lease area in respect of non-coal mine lease</p> <p>≤150 ha of mining lease area in respect of coal mine lease</p>	<p>General Conditions shall apply except:</p> <p>(i) for project or activity of mining of minor minerals of Category ‘B2’ (up to 5 ha of mining lease area);</p> <p>(ii) river sand mining projects on account of inter-state boundary.</p> <p>Note:</p> <p>(i) Mineral prospecting is exempted. ”;</p>

(j) after Appendix VI, the following appendices shall be inserted, namely:—

“APPENDIX VII

(See paragraph 3 A)

Qualifications and terms for the experts in DEIAA and DEAC

- 1. Qualification:** MA/M.Sc. Degree or B. Tech/ B.E./B. Arch. Degree or Degree in Law.
- 2. Experience:** A person fulfilling the above eligibility criteria with ten years of experience in ecology measurement/monitoring, analysis and interpretation of data in relation to river ecology/ life science in floral/faunal management/forestry/wildlife/mining/geology expert/ environmental economics/socio economics or a doctoral degree (Ph.D.) in concerned field with five years’ experience.
- 3. Age:** Not exceeding seventy years; in the event of non-availability of such a person, the age may be relaxed by five years.
- 4. Tenure:** The maximum tenure of expert members shall be for two terms of three years each.

APPENDIX VIII

(See paragraph 6)

FORM 1M

APPLICATION FOR MINING OF MINOR MINERALS UNDER CATEGORY ‘B2’

(I) Basic Information

- Name of the Mining Lease site:
- Location/site (GPS Co-ordinates):
- Size of the Mining Lease (Hectare):
- Capacity of Mining Lease (TPA):
- Period of Mining Lease:
- Expected cost of the Project:
- Contact Information:

(II) **Environmental Sensitivity**

S. No.	Areas	Distance in kilometer/Details
1	Distance of project site from nearest rail/road bridge over the concerned River, Rivulet, Nallah etc.	
2	Distance from Infrastructural facilities Railway line National Highway State Highway Major District Road Any Other Road Electric transmission line pole/tower Canal In-take for drinking water pump house Intake for Irrigation canal pumps	
3	Areas protected under international conventions, national or local legislation for their ecological, landscape, cultural or other related value	
4	Areas which are important or sensitive for ecological reasons - Wetlands, watercourses or other water bodies, coastal zone, biospheres, mountains, forests	
5	Areas used by protected, important or sensitive species of flora or fauna for breeding, nesting, foraging, resting, over wintering, migration	
6	Inland, coastal, marine or underground waters	
7	State, national boundaries	
8	Routes or facilities used by the public for access to recreation or other tourist, pilgrim areas	
9	Defence installations	
10	Densely populated or built-up area	
11	Areas occupied by sensitive man-made land uses (hospitals, schools, places of worship, community facilities)	
12	Areas containing important, high quality or scarce resources (ground water resources, surface resources, forestry, agriculture, fisheries, tourism, minerals)	
13	Areas already subjected to pollution or environmental damage. (those where existing legal environmental standards are exceeded)	
14	Areas susceptible to natural hazard which could cause the project to present environmental problems (earthquakes, subsidence, landslides, erosion, flooding or extreme or adverse climatic conditions)	
15	Is proposed mining site located over or near fissure/fracture for ground water recharge	

APPENDIX – IX

[See paragraph 7(i) (B)]

EXEMPTION OF CERTAIN CASES FROM BEING CONSIDERED AS MINING OF MINOR MINERALS

The following cases shall not be treated as mining operations for the purpose of requirement of prior environment clearance, namely:—

1. Extraction of ordinary clay or sand, manually, by the Kumhars (Potter) to prepare earthen pots as per their customs.
2. Extraction of ordinary clay or sand, manually, by earthen tile makers who prepare earthen tiles.
3. Removal of sand deposits on agricultural field after flood by farmers.

4. Customary extraction of sand and ordinary earth from sources situated in Gram Panchayat for personal use or community work in village.
5. Community works like de-silting of village ponds or tanks, construction of village roads, bunds undertaken in Mahatama Gandhi National Rural Employment and Guarantee Schemes and other Government sponsored schemes.
6. Dredging and de-silting of dams, reservoirs, weirs, barrages, rivers, and canals for the purpose of their maintenance and upkeep.

APPENDIX - X

[See paragraph 7 (iii) (a)]

PROCEDURE FOR PREPARATION OF DISTRICT SURVEY REPORT

The main objective of the preparation of District Survey Report (as per the Sustainable Sand Mining Guideline) is to ensure the following:-

Identification of areas of accretion/deposition where mining can be allowed; and identification of areas of erosion and proximity to infrastructural structures and installations where mining should be prohibited and calculation of annual rate of replenishment and allowing time for replenishment after mining in that area.

The report shall have the following structure:

1. Introduction
2. Overview of Mining Activity in the District
3. The List of Mining Leases in the District with location, area and period of validity.
4. Details of Royalty/Revenue Received in last three years.
5. Detail of Production of Sand/Bajari/minor mineral in last three years.
6. Process of Deposition of Sediments in the rivers of the District.
7. General Profile of the District
8. Land Utilization Pattern in the district: Forest, Agriculture, Horticulture, Mining etc.
9. Physiography of the District.
10. Rainfall: month-wise
11. Geology and Mineral Wealth.

In addition to the above, the report shall contain the following:

- (a) District wise detail of river or stream and other sand source.
- (b) District wise availability of sand/gravel/aggregate resources.
- (c) District wise detail of existing mining leases of sand and aggregates.

A survey shall be carried out by the DEIAA using Geological Department/ Irrigation Department/ Forest Department/ PWD/ Ground Water Boards/Remote Sensing Department/ Mining Department etc. in the district.

Drainage system with description of main rivers.

S.No.	Name of the river	Area drained (Sq. Km)	% of area drained in the district

Salient features of important rivers and streams:

S.No.	Name of the river/stream	Total length in the district (in Km)	Place of origin	Altitude at origin

Portion of the river/stream recommended for mineral concession	Length of area recommended for mineral concession (in kilometer)	Average width of area recommended for mineral concession (in meters)	Area recommended for mineral concession (in square meter)	Mineable mineral potential (in metric tonne) (60% of total mineral potential)

Mineral Potential (in metric ton)

Boulder	Bajari	Sand	Total mineable mineral

Annual deposition

S. No.	river/ stream	Portion of the river/stream recommended for mineral concession	Length of area recommended for mineral concession (in kilometer)	Average width of area recommended for mineral concession (in meters)	Area recommended for mineral concession (in square meter)	Mineable mineral potential (in metric tonne) (60% of total mineral potential)
Total for the district						

A Sub-Divisional Committee comprising of Sub-Divisional Magistrate, officers from Irrigation Department, State Pollution Control Board, Forest Department, Geology/mining officer should visit each site and make recommendation on suitability of site for mining or prohibition thereof.

Methodology adopted for calculating of mineral potential:

The mineral potential is calculated based on field investigation and geology of the catchment area of the river/streams. As per the site conditions and location, depth of minable mineral is defined. The area for removal of the mineral in a river or stream can be decided depending on geo-morphology and other factors, it can be 50 % to 60 % of the area of a particular river/stream. For example in some hill States mineral constituents like boulders, river born Bajri, sand up to a depth of one meter are considered as resource mineral. Other constituents like clay and silt are excluded as waste while calculating the mineral potential of particular river/stream.

APPENDIX - XI**[See paragraph 7 (iii) (b)]****PROCEDURE FOR ENVIRONMENTAL CLEARANCE OF MINING OF MINOR MINERALS IN CLUSTER**

The following procedure shall be followed for obtaining environmental clearance of mining of minor mineral projects in cluster, namely:-

- (1) The data provided by the States as per Sustainable Sand Mining Guidelines, 2015 shows that most of the mining leases for minor minerals is of lease area less than 5 hectare. It is also reported that, in hill States getting a stretch in river with area more than 5 hectare is very uncommon. So, the size of lease for minor minerals including river sand mining shall be determined by the States as per the circumstances.
- (2) The mining of minor minerals is mostly in clusters. The Environment Impact Assessment/Environment Management Plan (where in after referred to as the EIA/EMP) are required to be prepared for the entire cluster in order to cover all the possible externalities. These reports should cover carrying capacity of the cluster, transportation and related issues, replenishment and recharge issues, geo-hydrological study of the cluster area. The EIA /EMP report shall be prepared by the State or State nominated agency/Group of project proponents in the cluster/the project proponent in cluster.
- (3) There will be one public consultation for entire cluster after which the final EIA/EMP report for cluster shall be prepared.
- (4) EC shall be applied for and issued to the individual project proponent.
- (5) The details of cluster EIA/ EMP report shall be reflected in each EC of that cluster and DEAC, SEAC, and EAC shall ensure that mitigative measures emanating from the EIA/EMP study are fully reflected as EC conditions in the EC of individual project proponents of that cluster.

Schematic Presentation of Requirements on Environmental Clearance of Minor Minerals including cluster

Area of lease (Hectare)	Category of Project	Requirement of EIA/EMP	Requirement of Public Hearing	Requirement of EC	Who can prepare EIA/ EMP	Who will apply for EC	Authority to appraise/ grant EC	Authority to monitor EC compliance
EC Proposal of Sand Mining on the basis of individual mine lease								
0 – 5ha	‘B2’	Form –I, PFR and Approved Mine Plan	No	Yes	Project Proponent	Project Proponent	DEAC/ DEIAA	District Collector SPCB CPCB
>5ha and up to 50ha	‘B1’	Yes	Yes	Yes	Project Proponent	Project Proponent	SEAC/ SEIAA	MoEFCC Agency nominated by MoEFCC
50 ha and above	A	Yes	Yes	Yes	Project Proponent	Project Proponent	EAC/ MoEFCC	MoEFCC
EC Proposal of Mining of minor mineral in cluster situation								
Cluster of mine leases less than 5ha	‘B2’	Form –I, PFR and Approved Mine Plan	No	Yes	State, State Agency, Group of Project Proponents,	Project Proponent	DEAC/ DEIAA/	District Collector SPCB CPCB

					Project Proponent			MoEFCC Agency nominated by MoEFCC
Cluster of mine leases of any size with all individual lease less than 50ha	'B1'	Yes	Yes	Yes	State, State Agency, Group of Project Proponents, Project Proponent	Project Proponent	SEAC/ SEIAA	
Cluster of any size with any of the individual lease more than 50ha	'A'	Yes	Yes	Yes	State, State Agency, Group of Project Proponents, Project Proponent	Project Proponent	EAC/ MoEFCC	

APPENDIX - XII

[See paragraph 10 (iv)]

PROCEDURE FOR MONITORING OF SAND MINING

1 The security feature of T.P. shall be as under:

- Printed on IBA approved MICR paper.
- Unique Barcode.
- Unique QR code.
- Fugitive Ink Background.
- Invisible Ink Mark.
- Void Pantograph.
- Watermark.

2 Requirement at Mine Lease Site:

- Small Size Plot (Up to 5 hectare): Android Based Smart Phone.
- Large Size Plots (More than 5 hectare): CCTV camera, Personal Computer (PC), Internet Connection, Power Back up.
- Access control of mine lease site.
- Arrangement for weight or approximation of weight of mined out mineral on basis of volume of the trailer of vehicle used.

3 Scanning of Transport Permit or Receipt and Uploading on Server:

- Website: Scanning of receipt on mining site can be done through barcode scanner and computer using the software;
- Android Application: Scanning on mining site can be done using Android Application using smartphone. It will require internet availability on SIM card;
- SMS: T.P./Receipt can be uploaded on server even by sending SMS through mobile. Once T.P./Receipt get uploaded, an unique invoice code gets generated with its validity period.

4 Proposed working of the system:

The State Mining Department should print the T.P./Receipt with security features enumerated at Paragraph 1 above and issue them to the mine lease holder through the District Collector. Once these Transport

Permits or Receipts are issued, they would be uploaded on the server against that mine lease area. Each receipt should be preferably with pre-fixed quantity, so the total quantity gets determined for the receipts issued.

When the Transport Permit or Receipt barcode gets scanned and invoice is generated, that particular barcode gets used and its validity time is recorded on the server. So all the details of transporting of mined out material can be captured on the server and the Transport Permit or Receipt cannot be reused.

5 Checking On Route:

The staff deployed for the purpose of checking of vehicles carrying mined mineral should be in a position to check the validity of Transport Permit or Receipt by scanning them using website, Android Application and SMS.

6 Breakdown of Vehicle:

In case the Vehicle breakdown, the validity of Transport Permit or Receipt shall be extended by sending SMS by driver in specific format to report breakdown of vehicle. The server will register this information and register the breakdown. The State can also establish a call centre, which can register breakdowns of such vehicles and extend the validity period. The subsequent restart of the vehicle also should be similarly reported to the server/call centre.

7 Tracking of Vehicles:

The route of vehicle from source to destination can be tracked through the system using check points, RFID Tags, and GPS tracking.

8 Alerts/Report Generation and Action Review:

The system will enable the authorities to develop periodic report on different parameters like daily lifting report, vehicle log/ history, lifting against allocation, and total lifting. The system can be used to generate auto mails/SMS. This will enable the District Collector/Magistrate to get all the relevant details and will enable the authority to block the scanning facility of any site found to be indulged in irregularity. Whenever any authority intercepts any vehicle transporting illegal sand, it shall get registered on the server and shall be mandatory for the officer to fill in the report on action taken. Every intercepted vehicle should be tracked.

The monitoring of mined out mineral, environmental clearance conditions and enforcement of Environment Management Plan will be ensured by the District Collector and the State Pollution Control Board. The monitoring of enforcement of environment clearance conditions can be done by the Central Pollution Control Board, Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the agency nominated by the Ministry for the purpose.”.

[F. No. Z-11013/98/2014-IA-II (M)]

MANOJ KUMAR SINGH, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide notification number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and subsequently amended as follows:—

1. S.O. 1737(E), dated the 11th October, 2007;
2. S.O. 3067(E), dated the 1st December, 2009;
3. S.O. 695(E), dated the 4th April, 2011;
4. S.O. 2896(E), dated the 13th December, 2012;
5. S.O. 674(E), dated the 13th March, 2013;
6. S.O. 2204 (E), dated the 19th July 2013;
7. S.O. 2555 (E), dated the 21st August, 2013;
8. S.O. 2559(E), dated the 22nd August, 2013;
9. S.O. 2731(E), dated the 9th September, 2013;
10. S.O. 562(E), dated the 26th February, 2014;
11. S.O. 637(E), dated the 28th February, 2014;
12. S.O. 1599(E), dated the 25th June, 2014;

13. S.O. 2601(E), dated the 7th October, 2014;
14. S.O. 2600(E), dated the 9th October, 2014
15. S.O. 3252(E), dated the 22nd December, 2014;
16. S.O. 382(E), dated the 3rd February, 2015;
17. S.O. 811(E), dated the 23rd March, 2015;
18. S.O. 996(E), dated the 10th April, 2015;
19. S.O. 1142 (E), dated the 17th April, 2015;
20. S.O. 1141(E), dated the 29th April, 2015;
21. S.O. 1834 (E), dated the 6th July, 2015